भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 261
दिनांक 22 जुलाई, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

आईसीएमआर की अनुसंधान गतिविधियों में कुशल व्यक्तियों की नियुक्ति

261. डॉ. अजित माधवराव गोपछड़ेः

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सरकार द्वारा भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) को सर्वाधिक उन्नत अवसंरचनात्मक सुविधाओं तक पहुँच सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जाने का प्रस्ताव है तथा इसके बजट आवंटन को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) देश को भविष्य में किसी भी प्रकार के जैविक युद्ध के खतरों से बचाने और उसकी रक्षा प्रणाली को मजबूत करने के उद्देश्य से आईसीएमआर की अनुसंधान गतिविधियों में सर्वश्रेष्ठ प्रतिभाशाली और कुशल व्यक्तियों को आकर्षित करने के लिए सरकार द्वारा अब तक उठाए गए या प्रस्तावित कदम क्या हैं; और

(ग) क्या आईसीएमआर संयुक्त अनुसंधान परियोजनाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थानों के साथ सहयोग करने की योजना बना रहा है?

उत्तर
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री प्रतापराव जाधव)

(क): भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (ICMR) के देश भर में 28 संस्थान हैं, जिनमें अत्याधुनिक सुविधाएं हैं, जो जैव चिकित्सा अनुसंधान के निर्माण, समन्वय और संवर्धन के लिए कार्यरत हैं। देश को जन स्वास्थ्य आपात स्थितियों से निपटने के लिए तैयार करने के दीर्घकालिक लक्ष्य के साथ, स्वास्थ्य प्रणालियों और संस्थानों की क्षमता विकसित करने हेतु प्रधानमंत्री - आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन (PM-ABHIM) शुरू किया गया है। इस योजना के अंतर्गत, ICMR के लिए जम्मू, डिब्रूगढ़, जबलपुर और बेंगलुरु में चार क्षेत्रीय राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान (NIV) और नागपुर में राष्ट्रीय वन हेल्थ संस्थान (National Institute of One Health) को मंजूरी दी गई है। पुणे में राष्ट्रीय ट्रांसलेशनल विषाणु विज्ञान एवं एड्स अनुसंधान संस्थान (ICMR-NITVAR) के सैटेलाइट केंद्र को भी मंजूरी दी गई है। दो मोबाइल बायोसेफ्टी लेवल 3 (BSL-3) वैन पहले ही खरीदी जा चुकी हैं और राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान (NIV) पुणे और क्षेत्रीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान केंद्र (RMRC) गोरखपुर में तैनात की जा चुकी हैं। इसके अलावा, 10 वायरल अनुसंधान

और नैदानिक प्रयोगशालाओं (वीआरडीएल) को संक्रामक रोग अनुसंधान और नैदानिक प्रयोगशालाओं (आईआरडीएल) में अपग्रेड करने के लिए शामिल किया गया है, और 5 वीआरडीएल को बायोसेफ्टी लेवल 3 (BSL-3) प्रयोगशालाओं में अपग्रेड करने के लिए शामिल किया गया है। PM-ABHIM योजना के अंतर्गत स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग (DHR) को 2021-22 से 2025-26 के लिए कुल 1670 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

आईसीएमआर के लिए आवंटन 2014-15 में 820.00 करोड़ रुपये से बढ़कर 2025-26 में 3125.50 करोड़ रुपये हो गया है, यह वृद्धि लगभग 281 प्रतिशत है, जो स्वास्थ्य अनुसंधान को आगे बढ़ाने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को मजबूत करती है।

(ख): भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (ICMR) ने बताया है कि वह भारत में स्वास्थ्य अनुसंधान को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिभाओं की नियुक्ति और विकास को प्राथमिकता दे रही है। इसके बहुआयामी प्रयासों में लक्षित भर्ती, लचीले अनुसंधान अवसर और युवा पेशेवरों, शोधकर्ताओं और वैज्ञानिकों के लिए विशेष रूप से तैयार किए गए उन्नत प्रशिक्षण कार्यक्रम शामिल हैं।

आईसीएमआर ने अपने इंट्राम्यूरल और एक्स्ट्राम्यूरल अनुसंधान अनुदानों को संशोधित किया है, जिससे वे अधिक प्रतिस्पर्धी बन गए हैं और एक्स्ट्राम्यूरल अनुदानों का आकार भी बढ़ गया है। संरचित प्रशिक्षण और मार्गदर्शन दृष्टिकोण की शुरुआत की गई है। इंट्राम्यूरल प्रोग्राम के माध्यम से प्रारंभिक करियर लघु अनुसंधान सहायता अनुदान (इग्निशन ग्रांट) भी दिए जाते हैं। प्रति परियोजना 30 लाख रुपये का यह अनुदान अधिकतम 3 वर्षों की अवधि के लिए दिया जाता है। इसका उद्देश्य नवनियुक्त वैज्ञानिकों को अपनी शोध साख स्थापित करने और भविष्य में वित्त पोषण प्राप्त करने हेतु क्षमता निर्माण में सहायता करना है ।

इन प्रयासों को मानव संसाधन विकास (एचआरडी) योजना नामक एक समर्पित प्रतिभा और अनुसंधान क्षमता निर्माण योजना के माध्यम से और अधिक सुदृढ़ किया गया है। स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग (DHR) ने एचआरडी योजना के तहत कुछ कार्यक्रमों का पुनर्गठन किया है जिससे उनकी प्रभावशीलता और पहुंच बढ़ गयी है। स्टार्ट-अप अनुदान कार्यक्रम के लिए पात्रता मानदंड को व्यापक बनाया गया है, मासिक फैलोशिप की संख्या बढ़ाई गई है और एमबीबीएस/बीडीएस छात्रों के लिए शॉर्ट टर्म स्कॉलरशिप (एसटीएस) (1000 से 2000 तक), एमडी/एमएस थीसिस सपोर्ट (100 से 500 तक) और पीएचडी के लिए फैलोशिप (300 से 500 तक) जैसे कार्यक्रमों में सीटों की संख्या बढ़ाई गई है। महिला शोधकर्ताओं को प्रोत्साहित करने के लिए महिला वैज्ञानिक फैलोशिप प्रदान की जाती है। देश में नैदानिक शोधकर्ताओं की संख्या बढ़ाने के लिए 2024 में यंग मेडिकल फैकल्टी-पीएचडी कार्यक्रम शुरू किया गया। वित्तीय वर्ष 2024-25 में रिकॉर्ड संख्या कुल 4291 फेलोशिप का समर्थन किया गया है। इसके अलावा, एसीएसआईआर-आईसीएमआर सहयोग से एक नया चिकित्सा अनुसंधान संकाय (एफ एम आर) भी बनाया गया है । पहले वर्ष में, एफ एम आर में 140 पीएचडी छात्रों ने दाखिला लिया। बाहर के चिकित्सा वैज्ञानिकों के अलावा, आईसीएमआर के चिकित्सा वैज्ञानिकों ने भी एफ एम आर में पीएचडी के लिए नामांकन कराया है।

(ग): भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (ICMR) ने सूचित किया है कि उसके विभिन्न अंतरराष्ट्रीय संगठनों/एजेंसियों के साथ सहमति ज्ञापन (MoU) हैं। यह संयुक्त राज्य अमेरिका (स्वास्थ्य और मानव सेवा विभाग-DHHS, अंतर्राष्ट्रीय एड्स वैक्सीन पहल-IAVI), स्वीडन (फोर्टे), जर्मनी (जर्मन रिसर्च फाउंडेशन), फ्रांस (फ्रेंच राष्ट्रीय स्वास्थ्य और चिकित्सा अनुसंधान संस्थान-INSERM), दक्षिण कोरिया (बेसिक साइंस संस्थान-IBS), स्विट्जरलैंड (उपेक्षित रोगों के लिए औषधि पहल- DNDi , वैश्विक एंटीबायोटिक अनुसंधान और विकास भागीदारी-GARDP, स्विस राष्ट्रीय विज्ञान फाउंडेशन-SNSF), नेपाल (नेपाल स्वास्थ्य अनुसंधान परिषद-NHRC) और थाईलैंड (चिकित्सा विज्ञान विभाग-DMS) आदि देशों के संस्थानों के साथ भी सहयोग करता है। ये सहयोग विभिन्न तरीकों से पारस्परिक रूप से पहचाने गए क्षेत्रों में किए जाते हैं जैसे: (i) संयुक्त अनुसंधान परियोजनाएं; (ii) संयुक्त कार्यशालाएं/संगोष्ठियां और (iii) अनुमोदित सहयोगी परियोजनाओं के अंतर्गत वैज्ञानिकों का आदान-प्रदान।

*****